क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 02 अंक: 33, सोमवार, 25 फरवरी, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

पुलवामा आतंकी हमले का बदला जरूर लेगी मोदी सरकार: शाह

रामनाथपुरम : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) जवानों की शहादत का बदला जरूर लेगी। शाह ने आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से यहां 'शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन' को संबोधित करते हुए कहा कि सीआरपीएफ जवानों की शहादत का बदला जरुर लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतात्रिक गठबंधन ने आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपना रखी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में देश की रक्षा करते समय तमिलनाडु के दो वीर बांकुरों ने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने कश्मीर में शहीद हुए जवानों को बहादुरी को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, मोदी सरकार हमारे जवानों की शहादत का बदला लेकर रहेगी।

खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट, मुंबई रेलवे को आतंकी हमले का खतरा

मुंबई : देश की खूफियां एजेंसियों ने मुंबई रेलवे को अलर्ट भेजते हुए आतंकी हमले की आशंका जताई है। खुफिया सूचना के अनुसार, लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी समुद्री रास्ते से मुंबई में प्रवेश कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आतंकी रेलवे को अपना निशाना बना सकते हैं। लिहाजा सभी स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और रायगढ़ के समुद्र तट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियों की ओर से दी गई चेतावनी के बाद रेलवे सतर्क हो गई है। वहीं जगह-जगह चैकिंग भी कराई जा रही है। खास तौर से दिल्ली से आने वाले मेल-एक्सप्रेस में, एक बम निरीक्षक और एक डॉग स्क्वाड को जांच के आदेश दिए गए हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि अगर उन्हें कोई लावारिस सामान या संदिग्ध बैग मिलता है तो उसकी जानकारी आरपीएफ/जीआरपी के जवानों को दी जाए। साथ ही यात्रियों से अफवाह नहीं फैलाने और पुलिस जांच में सहयोग देने के लिए भी कहा गया है।

आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए होना होगा एकजुट: मोदी

सोल।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 'समय आ गया है' कि मानवता में विश्वास रखने वालों को एक साथ मिलकर आतंकवाद के नेटवर्क और उनके वित्तपोषण की जड़ों को उखाड़ फेंकना होगा और आतंकवाद की विचारधारा तथा उसके प्रोपेगेंडा के खिलाफ एकजुट होना होगा। मोदी ने शुक्रवार को दक्षिण कोरिया के प्रतिष्ठित सोल शांति पुरस्कार ग्रहण करने के बाद जनसमूह को संबोधित हुए यह बात कही। उन्होंने कहा , ऐसा करके ही हम नफरत की जगह सद्भाव, विनाश की जगह विकास, हिंसा और प्रतिशोध के स्थान पर शांति पैदा कर सकेंगे।÷ उन्होंने कहा, अच्छी शुरुआत करने से आधी लड़ाई जीत ली जाती है। इससे पहले मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, अब समय आ गया है कि वैश्विक समुदाय बातों से आगे बढ़कर इस समस्या के विरोध में एकजुट होकर कार्रवाई करे।÷ इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 14 फरवरी को पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का नाम लेते हुए कहा कि इस तरह के निंदनीय आतंकवादी हमले के साजिशकर्ताओं, संयोजको, वित्तपोषकों और प्रायोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर पुलवामा हमले की निंदा की और पाकिस्तान से आतंकवादी संगठनों के खिलाफ निर्णयाक कदम उठाने की बात कही। सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और पुलवामा हमले के संदर्भ में भारत का सहयोग करने की अपील की।

150 दिन में दो करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड जारी

नई दिल्ली ।

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना 'आयुष्मान भारत' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदु भूषण ने आज बताया कि हर दिन बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं, महज 150 दिन में दो करोड़ कार्ड जारी किये गये हैं और अब तक देश भर के 15,000 अस्पताल इससे जुड़े हैं, जिनमें से 15 फीसदी निजी अस्पताल हैं। भूषण ने मेडिकल फेयर इंडिया 2019 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करने के मौके पर कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखी है। केंद्र सरकार ने देश में हेल्थकेयर के पूरे माहौल के सुदृढ़ीकरण के लिए निवेश बढ़ाकर ढाई प्रतिशत किया है। आयुष्मान भारत योजना इसी दिशा में की गयी एक पहल है। वैश्विक हेल्थकेयर क्षेत्र देश की इस महत्वाकांक्षी योजना पर बारीकी से नजर बनाये हुए है। उन्होंने कहा कि शुरुआती चरण से ही हर दिन लाखों लोग आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहे हैं। शनिवार को योजना के पाँच महीने पूरे हो रहे हैं और इस अवधि में दो करोड़ कार्ड जारी किये गये हैं। हर दिन चार-पाँच लाख कार्ड जारी किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजी और सरकारी अस्पतालों के सामंजस्य में ही इस योजना का भविष्य है। मैं सभी संस्थानों से आग्रह करता हूँ कि दूर से परिवर्तन की प्रतीक्षा न करें बल्कि इससे जुड़ें और परिवर्तन में सहयोग दें।

अगस्ता वेस्टलैंड : राजीव सक्सेना को राहत, अंतरिम जमानत 25 फरवरी तक बढ़ी

नई दिल्ली ।

दिल्ली में एक अदालत ने शुक्रवार को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में दुबई निवासी उद्योगपति राजीव सक्सेना की अंतरिम जमानत 25 फरवरी तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सक्सेना की नियमित जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा। सक्सेना चूंकि मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का सहयोग कर रहा है, इसलिए ईडी ने स्वास्थ्य आधार पर दी गई सक्सेना की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। सक्सेना ने अदालत को बताया था कि वह पीठ के दर्द, सुन्नपन और पैरों में भारी के साथ-साथ कई अन्य समस्याओं से पीड़ित है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की सुरक्षा एजेंसियों ने 30 जनवरी को कॉर्पोरेट लॉबीस्ट दीपक तलवार के साथ सक्सेना को उसके दुबई स्थित आवास से गिरफ्तार कर उसी रात भारत प्रत्यर्पित कर दिया था। ईडी के अनुसार, अगस्ता वेस्टलेंड के पक्ष में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के ठेके को प्रभावित करने के लिए अधिवक्ता गौतम खेतान के साथ मिलकर सक्सेना ने विभिन्न राजनेताओं, प्रशासनिक

अधिकारियों और भारतीय वायु सेना के अधिकारियों को रुपये देने के लिए धन शोधन करने के लिए दुनियाभर में कॉरपोरेट संरचना उपलब्ध कराई थी।सक्सेना का नाम उसकी पत्नी शिवानी के खिलाफ दायर आरोपपत्र में लिखा गया था। शिवानी ईडी से गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर बाहर हैं।

प्रधानमंत्री मोदी को साउथ कोरिया ने दिया सियोल शांति पुरुस्कार

सियोल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अंतरराष्ट्रीय सहयोग में योगदान देने तथा वैश्विक आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए यहां शुक्रवार को 2018 का प्रतिष्ठित सियोल पीस प्राइज प्रदान किया गया। यहां आयोजित एक भव्य समारोह में मोदी को यह पुरस्कार सियोल पीस प्राइज फाउंडेशन ने प्रदान किया। इस अवसर पर मोदी के जीवन तथा उनकी उपलब्धियों पर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। मोदी को यह पुरस्कार देते वक्त पुरस्कार समिति ने अपने संभाषण में भारतीय तथा वैश्विक अर्थ व्यवस्थाओं में वृद्धि में उनके योगदान को स्वीकार किया। अमीर और गरीब के बीच की सामाजिक तथा आर्थिक खाई को कम करने के लिए 'मोदीनॉमिक्स' को श्रेय दिया। साथ ही समिति ने अन्य देशों के साथ सक्रिय नीति के जरिए क्षेत्रीय तथा वैश्विक शंति के क्षेत्र में उनके योगदान को भी श्रेय दिया। यह सम्मान पाने वाले मोदी 14वें व्यक्ति हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल जैसी जानी मानी हस्तियां तथा संगठन यह पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं।

इस पुरस्कार की स्थापना सियोल में आयोजित 24वें ओलंपिक खेलों की सफलता के जश्न में 1990 में की गई थी।

जम्मू-कश्मीर: 24 घंटे बाद सोपोर में मुठभेड़ खत्म, दोनों आतंकी ढेर

बारामुला ।

उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले में पिछले 24 घंटे से आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को मारकर उनके पास से एके-47 राइफल और गोला बारूद बरामद किया हैं। फिलहाल मारे गए आतंकियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। डीआईजी साउथ कश्मीर अतुल गोयल के अनुसार, इस मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे। इससे पहले गुरुवार को ही सुरक्षाबलों को सोपोर के वारपोरा इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने के इनपुट मिला थे। जिसके बाद सेना की 22 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर), सीआरपीएफ और पुलिस व एसओजी ने वारपोरा इलाके की घेराबंदी कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। इस बीच यहां एक मकान में छिपे आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों की गोलीबारी के बाद जवाबी कार्रवाई से मुठभेड़ शुरू हो गई और एक मकान को चारो ओर से घेर लिया।

इसके बाद इलाके में तत्काल सीआरपीएफ और एसओजी की टीमों को भेजकर घेराबंदी की गई। प्रशासन द्वारा इलाके में मुठभेड़ शुरू होने के साथ ही सोपोर और आस-पास के इलाकों में मोबाइल, इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई। कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए धारा 144 भी लागू कर दिया गया ताकि किसी भी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके।

इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा बेहद जरूरी: प्रसाद

नयी दिल्ली।

डिजिटलीकरण और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के बीच भारत को अपने डिजिटल प्लेटफार्म की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने शुक्रवार को यह बात कही। प्रसाद ने कहा कि डिजिटल मंचों की बुनियाद में ही साइबर सुरक्षा ढांचा उसके साथ होना चाहिए। प्रसाद ने वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते डिजिटल प्रभाव और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि वह साफ्टवेयर उत्पाद नीति पर भी जोर दे रहे हैं। प्रसाद ने विभिन्न श्रेणियों में 'डिजिटल इंडिया' पुरस्कार वितरित करने के बाद कहा, ''हम भारत को एक तेज तर्रार डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत सिर्फ सेवाओं की पेशकश नहीं करता है, बल्कि लोगों को आईटी और संबद्ध क्षेत्रों में कारोबार के लिए उपभोक्ताओं का आधार भी उपलब्ध कराता है। मंत्री ने कहा कि डिजिटल मंचों और प्रणाली की सुरक्षा सबसे जरूरी चीज है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ की आबादी के साथ भारत में डेटा विश्लेषण का एक प्रमुख केंद्र बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि डेटा राष्ट्रीय संपत्ति और इसका अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। एजेंसी

तेलंगाना सरकार का ऐलान, पुलवामा शहीदों के परिजनों को देगी 25-25 लाख रुपए

हैदराबाद : तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 40 जवानों के परिजनों को शुक्रवार को 25-25 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। उन्होंने पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) आतंकवादी संगठन द्वारा किए गए आतंकी हमले की निंदा करने के लिए राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव को पेश करते हुए यह घोषणा की। सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित कर दिया। इस दौरान सदन ने दो मिनट का मौन भी रखा। बजट सत्र के लिए सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पेश किया और हमले को 'अमानवीय' और 'बर्बर' करार दिया। उन्होंने कहा, 'यह राष्ट्र पर हमला था।' और फिर शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। नेता प्रतिपक्ष मल्लू भट्ठी विक्रमारका ने कहा कि पीड़ितों के परिवारों के साथ पूरा देश एकजुट है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के विधायक अहमद बालाला और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक राजा सिंह ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया और हमले की निंदा की।

कश्मीरियों पर हमले: शीर्ष अदालत ने तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश, महबूबा, उमर ने स्वागत किया

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीरियों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं के मद्देनजर शुक्रवार को 11 राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने जिन राज्यों में कश्मीरियों को धमकी देने तथा उनके खिलाफ हिंसा की घटनाएं हुई हैं, उनसे जवाब मांगा। पीठ ने निर्देश दिया कि पीट-पीटकर हत्या की घटनाओं से निपटने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये पुलिस अधिकारी अब कश्मीरियों पर हमलों के मामलों से निपटने के लिए जिम्मेदार होंगे। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ ही दिल्ली के पुलिस आयुक्त को कश्मीरी छात्रों सहित कश्मीरियों को धमकी देने, उनसे मारपीट करने और उनका सामाजिक बहिष्कार करने की घटनाओं की रोकथाम के लिये कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। पीठ ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय को इसका व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया ताकि कश्मीरी लोग इस तरह की घटना होने की स्थिति में नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकें। पीठ ने कहा कि राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को कश्मीरी जनता और अन्य अल्पसंख्यकों को धमकी देने, उनसे मारपीट करने और उनका सामाजिक बहिष्कार करने जैसी घटनाओं को रोकने के लिये तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया जाता है। पीठ अधिवक्ता तारिक अदीब की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमे पुलवामा में 14 फरवरी को आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान मारे जाने की घटना के बाद कश्मीरियों के खिलाफ कथित रूप से हो रही इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिये केन्द्र और राज्यों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश का स्वागत किया। पीडीपी प्रमुख महबूबा ने ट्विटर पर कहा कि शीर्ष कोर्ट के इस आदेश पर राहत महसूस की कि यह सुनिश्चित हो कि जम्मू कश्मीर से बाहर मौजूद कश्मीरी छात्रों का उत्पीड़न या सामाजिक बहिष्कार नहीं हो। माननीय न्यायपालिका ने निर्णायक कदम उठाया लेकिन शर्मनाक है कि अन्य ने आराम से इसे नजरअंदाज कर दिया। नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष अब्दुल्ला ने कहा कि वह इस कदम के लिए उच्चतम न्यायालय के आभारी हैं लेकिन यह काम केन्द्र की सरकार को करना चाहिए था। अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, जो काम दिल्ली के निर्वाचित नेतृत्व को करना चाहिए था, उसे करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का आभार। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री इससे इंकार करने में लगे हैं और राज्यपाल धमकियां देने में व्यस्त हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का कदम उठाने पर धन्यवाद। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोन्साल्विज ने दावा किया कि यह याचिका दायर करने के बाद विभिन्न राज्यों में इस तरह के हमलों की दस से अधिक घटनायें हो चुकी हैं और इसलिए इन पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने के लिये तत्काल निर्देश देने की आवश्यकता है। केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि गृह मंत्रालय ने 17 फरवरी को ही राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में परामर्श जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है परंतु हम राज्यों को ऐसा निर्देश नहीं दे सकते कि ऐसी घटनाओं की स्थिति में किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। पीठ ने इन दलीलों का संज्ञान लेते हुये अपने पहले के फैसले का जिक्र किया जिसमे उसने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक जिले में भीड़ की हिंसा के मामलों से निबटने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नियुक्त करने को कहा था। पीठ ने कहा कि हाल ही में हुये आतंकी हमले की घटना के मद्देनजर ये पुलिस अधिकारी कश्मीरियों और अन्य अल्पसंख्यकों से जुड़ी ऐसी घटनाओं के मामलों को देखेंगे। पीठ इस मामले में अब बुधवार को आगे विचार करेगी। पुलवामा आतंकी हमले के बाद कश्मीरियों पर हुये हमले की घटनाओं के आलोक में दायर याचिका में केन्द्र और दूसरे प्राधिकारियों को नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और प्रत्येक राज्य में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में तत्काल ही राष्ट्रव्यापी हेल्पलाइन नंबर शुरू करने के साथ ही एक वेबसाइट पर राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील जिलों में नियुक्त नोडल अधिकारियों के संपर्क का विवरण उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है।

संपादकीय

नये दौर में रिश्ते

सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान की यात्रा ऐसे वक्त में हुई जब देश पाक समर्थित आतंकियों के हमले से उबरने की कोशिश में है। युवराज इससे पहले पाकिस्तान गये थे, लेकिन भारत की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए युवराज सीधे भारत आने के बजाय पहले स्वदेश गये फिर भारत आये। इससे जाहिर है कि युवराज भारतीय जनमानस की भावनाओं के प्रति संवेदनशील हैं। हालांकि, युवराज ने अपने बयान में पुलवामा हमले और पाक की भूमिका पर कुछ नहीं कहा, लेकिन स्वीकार किया कि अतिवाद व आतंकवाद दोनों देशों की समस्याएं हैं। उन्होंने इस दिशा में हर तरह का सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। इसमें खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान भी शामिल है। महत्वपूर्ण यह भी है कि प्रिंस सलमान की भारत यात्रा के दौरान पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। इसमें संरचनात्मक ढांचे, पर्यटन व आवास क्षेत्र में सहयोग करने का फैसला लिया गया। देश के इन्वेस्ट इंडिया और सऊदी अरब की जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के बीच निवेश संबंधी करार के अलावा सूचना व प्रसारण के क्षेत्र में समझौते हुए। भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले बड़े देशों में शुमार सऊदी अरब से रिश्ते को युवराज की यात्रा से नये आयाम मिलेंगे। दरअसल, सऊदी अरब से कारोबारी व कूटनीतिक रिश्तों के अलावा भारत की बड़ी श्रमशील आबादी सऊदी अरब के विकास में योगदान कर रही है। दोनों देशों के बीच सालाना कारोबार पाकिस्तान के मुकाबले कई गुना है, मगर एक इस्लामिक देश के नाते पाक से सामरिक रिश्ते ज्यादा करीब हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में एक तबका मानता है कि जब भारत-पाक रिश्ते बेहद खराब दौर में हैं तो सऊदी अरब इन्हें सामान्य बनाने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। दरअसल, क्राउन प्रिंस को प्रगतिशील अर्थव्यवस्था समर्थक माना जाता है। वे वर्ष 2030 तक एक नये विकसित सऊदी अरब का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसके चलते उनके साथ भारत आये प्रतिनिधिमंडल ने आईटी और पेट्रोलियम कंपनियों से करार किये। एक ओर युवराज जहां आधुनिक तकनीक के लिए भारत से रिश्तों को सुधार करके निवेश बढ़ा रहे हैं, वहीं पाक में निवेश करके चीन के बाजार तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश में हैं। इसके बावजूद वे भारत व पाक के बिगड़ते रिश्तों को सुधारने में कोई बड़ी भूमिका निभा पायेंगे, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल, इतना तो तय है कि युवराज के सऊदी अरब 2030 विजन के प्रारूप को हकीकत में बदलने में भारतीय प्रतिभाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

एक ओर युवराज जहां आधुनिक तकनीक के लिए भारत से रिश्तों को सुधार करके निवेश बढ़ा रहे हैं, वहीं पाक में निवेश करके चीन के बाजार तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश में हैं। इसके बावजूद वे भारत व पाक के बिगड़ते रिश्तों को सुधारने में कोई बड़ी भूमिका निभा पायेंगे, यह आने वाला वक्त ही बताएगा।

निकट आते भारत-अमेरिका

अर्थव्यवस्था/ जयंतीलाल भंडारी

लाइसेंस और नियामकीय बाधाएं खत्म की गई हैं, और नये हाईटेक समाधान अपनाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से भारत ने अमेरिका के साथ कारोबार संबंधों की अहमियत को समझा है, और उपयुक्त रूप से अमेरिका के साथ कारोबार संबंधों के तनाव को कम करने के लिए आगे बढ़ा है। पिछली 14 फरवरी को अमेरिका और भारत सरकार के आधिकारियों और सीईओ के बीच कारोबार और निवेश को लेकर मतभेदों के समाधान के लिए उच्चस्तरीय बातचीत हुई। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने अमेरिका-भारत सीईओ फोरम को वीडियो के माध्यम से संबोधित किया।

यकीनन जहां एक ओर भारत और अमेरिका के बीच कारोबार संबंधों में तनाव में कमी लाने का परिदृश्य दिखाई दे रहा है, वहीं नियंतग्र आर्थिक अध्ययनों के तहत भारत और अमेरिका के बीच कारोबार बढ़ने की खासी संभावनाओं की रिपोर्टस भी प्रस्तुत हो रही हैं। वित्तीय सेवा परामर्श कंपनी पीडब्लयूसी और इंडो-अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स की एक साझा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018-19 में भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय कारोबार 100 अरब डॉलर से कुछ अधिक है, वह निकट भविष्य में बढ़कर 500 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच आने-जाने वाले लोगों की परस्पर यात्राओं में इजाफा हुआ है। दोनों देशों के बीच कारोबार संबंध बढ़ाने के लिए प्रयास बढ़ाए गए हैं। आतंकवाद से मिलकर लड़ने और व्यापार बढ़ाने के लिए भी पहल की जा रही है। इस अध्ययन रिपोर्ट में अंतरिक्ष, रक्षा, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, बीमा, रसायन, भारत में मालगाड़ियों के लिए विशेष मार्ग परियोजनाएं, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों को बड़ी संभावना वाले क्षेत्र बताया गया है। इसमें कहा गया है कि इससे ना केवल घरेलू वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा बल्कि विश्व के एक व्यावसायिक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी। बंदरगाह, आंतरिक जलमार्ग, खनिज तेल एवं गैस, औषधि और डिजिटलीकरण परियोजना क्षेत्र का भी उल्लेख किया गया है। यह भी कहा गया है कि ये क्षेत्र भारत सरकार और उद्योग जगत के मिले-जुले प्रयास से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कारोबारी गतिविधियां इस समय सर्वकालिक तीव्र स्तर पर हैं। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को नियंतग्र कंपनियों के लिए खोला है, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में ढील दी गई है। लाइसेंस और नियामकीय बाधाएं खत्म की गई हैं, और नये हाईटेक समाधान अपनाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से भारत ने अमेरिका के साथ कारोबार संबंधों की अहमियत को समझा है, और उपयुक्त रूप से अमेरिका के साथ कारोबार संबंधों के तनाव को कम करने के लिए आगे बढ़ा है। पिछली 14 फरवरी को अमेरिका और भारत सरकार के आधिकारियों और सीईओ के बीच कारोबार और निवेश को लेकर मतभेदों के समाधान के लिए उच्चस्तरीय बातचीत हुई। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने अमेरिका-भारत सीईओ फोरम को वीडियो के माध्यम से संबोधित किया। साथ ही भारत के वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु के साथ टेलीफोन पर भारत-अमेरिका कारोबार पर वार्तालाप किया। इस द्विपक्षीय वार्ता में रोजगार अवसरों में वृद्धि और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे मुद्दे मुख्य बिंदु रहे। अमेरिका और भारत ने वित्तीय सेवा, स्वास्य देखरेख और सुरक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय कारोबार और निवेश बढ़ाने के लिए तीन विशेष ग्रुप बनाने का निर्णय लिया। खास बात यह भी रही कि डाटा संग्रहण, कारोबारी असंतुलन कम करना, भारत की प्रस्तावित ई-कॉमर्स नीति पर अमेरिकी चिंता और दोनों देशों द्वारा एक दूसरे पर लगाए जा सकने वाले प्रतिशोधात्मक शुल्कों जैसे मसलों को बातचीत में शामिल नहीं किया गया। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच हुई इस बातचीत में अमेरिका ने अपनी कारोबारी योजना में ''तरजीह की सामान्य पण्याली-जनरलाइज्ड सिस्टम प्रेफरेंस (जीएसपी) को रद्द करने के विचार को आगे नहीं बढ़ाया है, जिसके माध्यम से 2000 भारतीय उत्पादों का शुल्क मुक्त कारोबार अमेरिका में करने की अनुमति मिली हुई है। अमेरिका से मिली व्यापार छूट के तहत भारत को करीब 5.6 अरब डॉलर के निर्यात पर शून्य सीमा शुल्क देना पड़ता है। जीएसपी के तहत भारत को एक विकासशील देश होने के नाते अमेरिका को बहुत सी वस्तुओं का शुल्क-मुक्त निर्यात करने का मौका मिलता है। आंकड़े बता रहे हैं कि इस योजना से अमेरिका को जितने राजस्व का नुकसान होता है, उसका एक चौथाई भारतीय निर्यातकों को प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि भारत-अमेरिका के बीच रणनीतिक और वाणिज्यिक बातचीत 2015 में शुरू हुई थी। दो सालाना बैठकों के बाद यह फैसला हुआ है कि कारोबार संबंधी मसलों को सुलझाने के लिए अलग से भारत-अमेरिका वाणिज्यिक बातचीत होगी। भारत-अमेरिका के बीच कारोबार संबंधी विवाद पिछले साल जुलाई, 2018 में उच्च स्तर पर पहुंच गया जब भारत ने 29 कृषि उत्पादों पर शुल्क लगाने की घोषणा कर दी। अमेरिका से आने वाले सेब, जैतून और अखरोट पर 50 प्रतिशत ज्यादा कर लगाने के अलावा कुछ औद्योगिक उत्पाद भी निशाने पर रहे हैं। भारत ने इन उत्पादों पर कर लगाने का फैसला 5 बार टाला है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है, और भारत को भी अपने आर्थिक लक्ष्यों के लिए अमेरिका की जरूरत है। अमेरिका भारत के लिए निवेश और तकनीक का महत्वपूर्ण स्रेत होने के साथ ही एक महत्वपूर्ण कारोबारी साझेदार भी है। भारत नियंतग्र निवेश के आकर्षक केंद्र के तौर पर उभरा है। जहां अमेरिका अब भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वहीं भारत दुनिया में सबसे तेज आर्थिक विकास दर वाला बड़ा देश है। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। इस देश का मध्यवर्ग तेजी से बढ़ रहा है, और अगले दो दशक में भारत में 50 करोड़ लोगों का विशाल बाजार मौजूद होगा। ऐसा विशाल उपभोक्ता-प्रधान भारत अमेरिका के लिए आर्थिक जरूरत बन गया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारत-अमेरिका के बीच कारोबारी और निवेश बातचीत के बाद कारोबार के मद्देनजर दोनों देश नजदीक आए हैं। अमेरिकी अधिकारियों और सीईओ के समक्ष यह बात अच्छी तरह रेखांकित हुई है कि भारत मजबूत आर्थिक ताकत और बड़े नियंतग्र बाजार के रूप में उभर रहा है, और अमेरिका एक ऐसा बाजार खोज रहा है, जो उसके लोगों को रोजगार दिला सके। हम आशा करें कि वित्तीय सेवा परामर्श कंपनी पीडब्लयूसी और इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स की साझा रिपोर्ट में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार निकट भविष्य में बढ़ते हुए 500 अरब डॉलर तक पहुंचने का जो शोध अनुमान प्रस्तुत किया गया है, उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए दोनों देश अपने कारोबारी तनाव को कम करते हुए तेजी से आगे बढ़ेंगे। इससे दोनों देशों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी मजबूत होंगी।

आज का राशीफल

मेष पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

वृषभ व्यावसायिक योजना सफल होगी। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।

मिथुन आर्थिक व व्यावसायिक समस्या रहेगी। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा।

कर्क राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। प्रणय संबंध मधुर होंगे। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें।

सिंह पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। यात्रा में अपने सामान के प्रति सचेत रहें चोरी या खोने की आशंका है। व्यर्थ के तनाव रहेंगे।

कन्या जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। आर्थिक संकट दूर होगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा।

तुला गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। व्यावसायिक योजना सफल होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। खानपान में संयम रखें। धन हानि की संभावना है। फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।

वृश्चिक व्यावसायिक दिशा में किए गए प्रयास फलीभूत होंगे। भाई या पड़ोसी का सहयोग रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।

धनु पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। पेत्र विकार की संभावना है। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे।

मकर बेरोजगार व्यक्तियोंको रोजगार मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। जारी प्रयास सार्थक होंगे।

कुम्भ जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।

मीन पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। अनावश्यक कार्यों में खर्च करना पड़ सकता है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। मांगलिक कार्यों में हिस्सेदारी रहेगी। व्यर्थ के तनाव भी मिलेंगे।

पाकिस्तान से निपटने के लिए पूरा देश एक

[डॉ. एके वर्मा]

असहमति की संवैधानिक आधारशिला पर स्थापित भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी खूबी यह है कि जब भी देश पर कोई गंभीर संकट आता है तो पूरा देश सुरक्षा और प्रतिरक्षा के मुद्दों पर एक स्वर में बोलता है। उड़ी, पठानकोट के जख्म से हम उबरे भी नहीं थे कि पाकिस्तान प्रायोजित पुलवामा आतंकी हमले ने देश को शोक, आक्रोश, उत्तेजना और प्रतिशोध की ज्वाला में धधका दिया है। एक स्वर में पाकिस्तान से बदले की मांग उठ रही है जो अत्यंत स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में भारत के कड़े रुख का इजहार कर दिया है और सेना को इसके लिए अधिकृत भी कर दिया है, लेकिन इस कठिन अवसर पर हम सभी को जोश में होश नहीं खोना है। क्या होगा सेना का जवाब, इसे हमें मीडिया में चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। नीति कहती है कि शत्रु पर उस समय प्रहार करना चाहिए जब वह उसका पूर्वानुमान न लगा सके। इस समय पाकिस्तान संभावित भारतीय प्रतिक्रिया के लिए पूरी तरह तैयार होगा। कोई भी कार्रवाई करने से पूर्व हमें आकलन करना जरूरी है कि किस प्रकार की कार्रवाई से हमें न्यूनतम और पाकिस्तान को अधिकतम नुकसान हो। देश के विभिन्न शहरों और कस्बों में हमारे लिए भावनात्मक एवं उत्तेजक प्रतिक्रिया करना आसान है, लेकिन सीमा पर तैनात वीर जवानों के बलिदानों का मूल्य चुकाना कठिन ही नहीं, नामुमकिन होता है। प्रत्येक युद्ध का एक अंत होता है और फिर दोनों ओर स्थितियां धीरे-धीरे सामान्य हो जाती हैं, लेकिन शहीदों के परिवार जिस अपूरणीय क्षति के साथ जीवन जीने को विवश होते हैं, उन्हें समाज भूल जाता है। वर्ष में एक बार हम सब उन शहीदों को याद जरूर करते हैं, लेकिन शहीदों के परिवारों के लिए परिस्थितियां फिर कभी भी सामान्य नहीं होतीं। यह भारत का दुर्भाग्य है कि उसे स्वतंत्रता के साथ-साथ पाकिस्तान जैसा एक नया और दुष्ट पड़ोसी भी मिला। शुरू से ही पाकिस्तान का रुख बहुत ही शत्रुतापूर्ण एवं नकारात्मक रहा है। 1971 में पूर्वी-पाकिस्तान को खोने के बाद से उसकी पूरी रणनीति छद्म युद्ध की हो गई। यह अफसोस की बात है कि पिछले 50 वर्षों में भारत ने उसकी कोई काट नहीं खोजी। हम हमेशा पाकिस्तान के प्रति मित्रतापूर्ण और सकारात्मक रुख रखते रहे और इस उम्मीद में जीते रहे कि शायद पाकिस्तान का दृष्टिकोण बदल जाए। बदले में पाकिस्तान हमेशा हमें जख्म देता रहा। कभी सैन्य हमले से तो कभी आतंकियों की वारदातों से, लेकिन भारत के धैर्य का यह एक परिणाम तो आया है कि पाकिस्तान को लेकर पूरे विश्व का नजरिया बदल गया है। आज ज्यादातर देश उसे आतंक को प्रश्रय देने वाले देश के रूप में देखते हैं जो पाकिस्तान के लिए न केवल शर्म की बात है वरन वह उसे आर्थिक बदहाली की और भी ले गई है। हालांकि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान में वास्तव में कई पाकिस्तान हैं। वहां की सरकार, सेना, आइएसआइ और आतंकवादियों के तमाम संगठनों के अलावा एक पाकिस्तान वहां की जनता का भी है जो भारत के प्रति उनसे भिन्न दृष्टिकोण रखता है, जो भारत की उपलब्धियों को लेकर चकित है और जो भारत के विकास को प्रत्यक्ष देखना चाहती है, लेकिन यह पाकिस्तान हम कभी देख ही नहीं पाते। पाकिस्तानी सरकार के कार्यों, अखबारों और टीवी में वह पाकिस्तान कभी दिखाई नहीं देता। इसलिए हमें पाकिस्तान की नापाक हरकतों का प्रत्युत्तर देने के लिए इसका बहुत ध्यान रखना होगा कि जहां हम पाकिस्तानी सरकार, सेना, आइएसआइ और आतंकवादियों को चोट पहुंचाएं वहीं पाकिस्तान की अमन पसंद जनता का भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण न खोएं। यह इसलिए और भी जरूरी है कि यदि कभी आगे चल कर वृहत्तर भारत की अवधारणा सार्थक होती है तो पाकिस्तानी जनता का भारतीय जनता और भारतीय लोकतंत्र से ताल-मेल भी बनाया जा सके। जब पुलवामा जैसे कांड होते हैं तब हम सबके सब्र का बांध जैसे टूट सा जाता है। पूरा देश सेना के संभावित कदमों पर चर्चा करता रहेगा, लेकिन यह जरूर है कि सेना को त्रिआयामी रणनीति अपनानी होगी। उसे तात्कालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदम उठाने होंगे। पाकिस्तान के बारे में और भी कई संवेदनशील कारक हमारे देश के अंदर और बाहर मौजूद हैं। उनकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती। पाकिस्तानी लोकतंत्र तो एक छद्म लोकतंत्र है जिसमें सरकार पूर्णत: सेना और आतंकियों के चंगुल में है, लेकिन भारत को तो विशुद्ध लोकतांत्रिक तरीके से ही पाकिस्तान और उससे जुड़े अन्य अनेक पहलुओं से निपटना है। लोकतंत्र की जरूरत है कि सरकार और सेना के इस प्रयास को जनता केसभी वर्गों का पूर्ण समर्थन हो। भावनाओं की अभिव्यक्ति में प्राय: कुछ अति-उत्साही युवक और संगठन तोड़-फोड़ और हिंसक विरोध-प्रदर्शन पर उतारू हो जाते हैं जिसमें वे अपने ही साधनों को नुकसान पहुंचाते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक प्रश्न-चिन्ह लगा देते हैं। हमें इसमें से बदलाव करना होगा। अपने विरोध और प्रतिक्रिया को सकारात्मक बनाना होगा। इसके लिए हमें ज्यादा काम करना होगा। सामाजिक सद्भाव कायम रखना होगा। अपनी आमदनी का एक हिस्सा शहीदों के लिए बने कोष में लगातार दान करना होगा और गंभीर एवं शालीन विमर्श द्वारा पाकिस्तान जैसी समस्या का स्थाई समाधान भी ढूंढ़ना होगा। चूंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा है कि 130 करोड़ देशवासियों का खून खौल रहा है इसलिए संकट की इस घड़ी में हमसे कोई भी ऐसा काम न करे जिससे समाज के किसी भी वर्ग में उपेक्षित या असहज होने का भाव आए। हां, यह जरूर है कि हमें राष्ट्र विरोधी ताकतों और विदेशी एजेंटों से सावधान रहने की जरूरत होगी। यह इसलिए और भी उल्लेखनीय है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। यह भी अच्छा है कि विपक्षी दल चुनावी नफा-नुकसान को इस राष्ट्रीय संकट से नहीं जोड़ रहे हैं। जहां अमेरिका में सरहद की समस्या पर राष्ट्रपति को विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के विरोध के चलते आपातकाल लगाना पड़ा वहीं भारत में सरहद पर उपजी समस्या के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी को संपूर्ण विपक्ष का पूरा सहयोग मिला। अब देखना है कि सरकार राजनयिक, सैनिक, आतंकी, वैश्विक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य अनेक पहलुओं पर भविष्य में किस तरह की तात्कालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियां अपनाती है जिससे पाकिस्तान की रोज-रोज की किच-किच से हमें निजात मिल सके और हम विकास एवं राष्ट्र-निर्माण के काम में शांति से मशगूल हो सकें।

(लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक हैं)

विचार मंथन

आर्थिक चोट पहुंचाकर भी बन सकते हैं कई दबाव

जयंतीलाल भंडारी, अर्थशास्त्री

जहां तक व्यापार की बात है, पिछले कुछ समय में भारत ने पाकिस्तान को हर तरह की सुविधा और प्राथमिकता देकर आपसी कारोबार बढ़ाने का मौका दिया है। अब पुलवामा आतंकी हमले के बाद यह परिदृश्य पूरी तरह से बदलने का समय दिखाई दे रहा है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और इंटरनेशनल ट्रेड नियमों के आधार पर किसी भी देश को व्यापार में एमएफएन यानी सर्वाधिक तरजीही देश का दर्जा दिया जाता है। एमएफएन का दर्जा दिए जाने पर वह देश इस बात को लेकर आश्वस्त रहता है कि उसके द्वारा आयात किए जाने पर उसे आयात संबंधी विशेष रियायतें प्राप्त होंगी। साथ ही उसे व्यापार में नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को 1996 में एमएफएन का दर्जा दिया था। पाकिस्तान को जब यह दर्जा मिला, तो उसको अधिक आयात कोटा देने के साथ उत्पादों को कम ट्रेड टैरिफ पर बेचे जाने की छूट भी मिली। हालांकि 23 साल पहले भारत की ओर से पाक को दिया गया यह दर्जा अब तक एकतरफा है। पाकिस्तान ने भारत को ऐसा कोई दर्जा नहीं दिया है। पाकिस्तान ने वर्ष 2012 में भारत को एमएफएन का दर्जा देने का एलान किया था, लेकिन अभी तक उसने वह वादा नहीं निभाया है। पाकिस्तान को एमएफएन का दर्जा देने के बाद भी भारत के साथ उसका आपसी कारोबार नहीं बढ़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच 2017-18 में द्विपक्षीय व्यापार कारोबार 2.38 अरब डॉलर का हुआ, जो भारत के कुल वैश्विक कारोबार का महज 0.3 फीसदी रहा। पाकिस्तान को किया जाने वाला निर्यात 1.9 अरब डॉलर, यानी भारत के कुल निर्यात का 0.63 फीसदी रहा। भारत में पाकिस्तान से होने वाला आयात 48 करोड़ डॉलर है, जबकि भारत द्वारा जिन सार्क देशों श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान को यह दर्जा दिया गया है, उनके साथ भारत का विदेश व्यापार तेजी से बढ़ा है। वैसे भी इस समय पाकिस्तान भारी आर्थिक मुश्किल में है। वह एक बार फिर बेलआउट के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दिसंबर 2017 से अब तक पाकिस्तानी रुपये का चार बार अवमूल्यन हो चुका है। चीन पर बहुत अधिक निर्भरता ने पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि पाकिस्तान के पास अपने आयात बिलों का भुगतान करने के लिए कोई विशेष विदेशी जमा पूंजी शेष नहीं बची है। पाकिस्तान का निर्यात कम है और आयात इसका लगभग दोगुना है। पाकिस्तान पेट्रोलियम, इंडस्ट्रियल मटेरियल और खाद्य तेल जैसी जरूरी चीजों का आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान से निर्यात होने वाले कपास की कीमत लगातार घट रही है। एक ओर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली अमेरिकी आर्थिक मदद में काफी कमी आई है। इसमें और कटौती का खतरा भी मंडरा रहा है। दूसरी ओर चीन से मिल रहे कर्ज पर भी उसे खासा ब्याज देना पड़ रहा है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर बिजली संकट का ग्रहण लगा हुआ है। आतंकवाद के चलते नकारात्मक छवि की वजह से पाकिस्तान में विदेशी निवेश लगातार घटता जा रहा है। यही वजह है कि पिछले दिनों जब सऊदी अरब के युवराज ने वहां निवेश की घोषणा की, तो पूरा पाकिस्तान जश्न मनाता दिखा। भारत द्वारा एमएफएन का दर्जा वापस लेने से पाकिस्तान की आर्थिक घेराबंदी की राह आगे बढ़ेगी। इसके अलावा भारत के पास एक विकल्प यह भी है कि वह नदी समझौतों पर पुनर्विचार करके दबाव बनाए। सरकार ने इस दिशा में सोचना शुरू भी कर दिया है। अभी भारत अपनी छह बड़ी नदियों का 80 फीसदी पानी पाकिस्तान को देता है। माना जाता है कि भारत शुरू से ही पाकिस्तान को समझौते से कुछ अधिक पानी दे रहा है। उसके दो तिहाई हिस्से में इन नदियों के पानी से सिंचाई होती है। ऐसे में, यदि भारत इन नदियों का कुछ अधिक पानी भारतीय क्षेत्र के लिए उपयोग में ले, तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

भारत-पाक विश्व कप मैच पर अभी कोई फैसला नहीं, सरकार से सलाह लेगा सीओएः राय

नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट का काम देख रही प्रशासकों की समिति (सीओए) ने पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप मुकाबले पर कोई भी फैसला नहीं लेने का निर्णय किया लेकिन कहा कि वह आईसीसी और अन्य सदस्यों से आग्रह करेगा कि ऐसे देश के साथ संबंध तोड़ दिए जाए जो आतंकवाद का गढ़ है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद ओल्ड ट्रैफर्ड में पाकिस्तान के खिलाफ 16 जून को होने वाले विश्व कप मुकाबले का बहिष्कार करने की मांग की जा रही है। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गये थे।

खिलाड़ियों से सलाह वाले जवाब पर नहीं दिया जवाब

मैच के संबंध में बढ़ती अटकलबाजियों को खत्म करने के लिए हुई बैठक में सीओए ने इस मामले पर बातचीत की लेकिन अभी कोई फैसला नहीं किया है। सीओए प्रमुख विनोद राय ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, 'सोलह जून तक की तारीख अभी बहुत दूर है। हम बाद में इस पर सरकार की सलाह के बाद फैसला करेंगे।' यह पूछने पर कि इस मुद्दे पर खिलाड़ियों से सलाह ली गई है तो राय ने नहीं में जवाब दिया। राय ने कहा, 'आईसीसी को ईमेल में हमने इस आंतकी हमले के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त कर दी हैं। हम उन्हें खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों की सुरक्षा के बारे में बतायेंगे कि इसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए।'

बोर्ड की तिमाही बैठक में उठेगा मुद्दा

उन्होंने संकेत दिया कि इस मामले को दुबई में होने वाली बोर्ड की तिमाही बैठक में उठाया जायेगा। उन्होंने कहा, 'दूसरा, हमें ऐसे देश से संबंध तोड़ देने चाहिए जहां से आतंकवाद पैदा होता है। हम उचित मंच पर अपनी चिंता जताएंगे।' आईसीसी की बैठक 26 फरवरी से दो मार्च तक आयोजित होगी। विश्व संस्था को भेजा गया ईमेल पीटीआई के पास है, इसमें बीसीसीआई ने कहा कि वह विश्व कप में जा रहे भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा के बारे में चिंतित है। इस पत्र के अनुसार, 'बीसीसीआई को आगामी आईसीसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों की सुरक्षा का डर है जिसमें क्रिकेट विश्व कप 2019 शामिल है।

गृहमंत्री के बयान पर टिप्पणी करने से राय का इनकार

आईसीसी के ज्यादातर सदस्यों (जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है) ने इस आंतकवादी हमले की निंदा की है और भारत के प्रति एकजुटता दिखाई है।' उन्होंने कहा, 'बीसीसीआई को भरोसा है कि आईसीसी और ईसीबी खिलाड़ियों, मैच अधिकारियों और भारतीय क्रिकेट के प्रशंसकों को आगामी विश्व कप में कड़ी सुरक्षा प्रदान करेगा।' राय ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने कहा, 'मैं इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हम सरकार से जो भी सलाह मशविरा करेंगे, वो बाद में करेंगे। कृपया इस बात को समझिये कि हमारे पास अभी तीन महीने का समय है। सरकार जो कुछ कहेगी, हम उसका पालन करेंगे। हम काल्पनिक परिस्थितियों पर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी फैसले पर नहीं पहुंचे हैं।' यह पहले से निश्चत है कि सीओए इस संबंध में कोई फैसला नहीं करेगा क्योंकि आईसीसी नियमों के अनुसार पाकिस्तान को प्रतिबंधित नहीं कर सकता।

शक्ति परीक्षण में जीत नहीं सकते

बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'अगर हम विश्व कप से पाकिस्तान को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पारित करने की कोशिश करें तो हम शक्ति परीक्षण में कभी भी जीत नहीं सकते। हमारे पास अभी आईसीसी में इतने मत नहीं हैं। बल्कि आईसीसी अध्यक्ष शशांक मनोहर के पास अपनी व्यक्तिगत क्षमता में इस समय बीसीसीआई से ज्यादा मत हैं।' यह भी दीगर है कि बीसीसीआई अधिकारी इसलिए भी चिंतित हैं कि इस कदम से वह 2021 चैम्पियंस ट्राफी और 2023 विश्व कप की मेजबानी अधिकार भी गंवा सकता है। सीनियर आफ स्पिनर हरभजन सिंह, पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन और सौरव गांगुली जैसे भारतीय क्रिकेटरों ने इस मैच के बहिष्कार की मांग की थी। वहीं महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर की राय इनसे अलग है जिन्होंने कहा कि भारत को मैच का बहिष्कार करके पाकिस्तान को अंक नहीं देने चाहिए। उन्होंने हालांकि द्विपक्षीय क्रिकेट संबंध जारी नहीं रखने की नीति पर कायम रहने की वकालत की थी। इसके अलावा सीओए ने एक अन्य फैसले में उत्तराखंड क्रिकेट में गुटों से एक साथ मिलकर महासंघ बनाने का आग्रह किया।

भारत-पाक मैच पर सचिन के तीखे तेवर, ये मुफ्त अंक देने का नहीं हराने का समय

नई दिल्ली। दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें आगामी विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलकर उसे दो अंक देना गवारा नहीं है क्योंकि इससे क्रिकेट महाकुंभ में इस चिर प्रतिद्वंद्वी को ही फायदा होगा। तेंदुलकर ने भी सुनील गावस्कर के विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि भारत के लिए विश्व कप में 16 जून को होने वाले मुकाबले से हटने के बजाय उसे हराना बेहतर होगा। पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों के मारे जाने के बाद इस मैच से हटने की मांग उठ रही है। तेंदुलकर ने एक वेबसाइट को एक बयान में कहा, 'भारत ने विश्व कप में हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है। अब फिर से उन्हें हराने का समय है। मैं निजी तौर पर उन्हें दो अंक देना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि इससे टूर्नामेंट में उन्हें मदद मिलेगी।' उन्होंने कहा, ''लेकिन मेरे लिये भारत सर्वोपरि है और मेरा देश जो भी फैसला करेगा मैं तहेदिल से उसका समर्थन करूंगा।' हरभजन सिंह और युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ियों ने जहां पाकिस्तान के पूर्ण बहिष्कार की मांग की है वहीं गावस्कर ने गुरुवार को कहा था कि अगर भारत अगर 16 जून को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलने का फैसला करता है तो यह उसकी हार होगी। विश्व कप ब्रिटेन में 30 मई से शुरू हो रहा है। शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट को संचालित करने वाली प्रशासकों की समिति ने कोई फैसला नहीं करने का निर्णय किया।

बिष्ट की घातक गेंदबाजी, भारत ने 66 रनों से जीता मैच

मुंबई ।

अनुभवी लेफ्ट आर्म स्पिनर एकता बिष्ट ने घातक गेंदबाजी करते हुए 25 रन पर चार विकेट लेकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में शुक्रवार को 66 रन से नाटकीय जीत दिला दी। भारत ने इस जीत के साथ तीन मैचों की इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत ने 49.4 ओवर में 202 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम एक समय तीन विकेट पर 111 रन बनाकर काफी सुखद स्थिति में थी लेकिन बिष्ट की घातक गेंदबाजी के चलते उसकी पूरी टीम 41 ओवर में 136 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड ने आखिरी सात विकेट मात्र 25 रन जोड़कर गंवा दिए। इंग्लैंड की तरफ से नताली शिवर ने 66 गेंदों में 44 रन और कप्तान हीथर नाइट ने 64 गेंदों में नाबाद 39 रन बनाए। बिष्ट ने आखिरी छह बल्लेबाजों में से चार को पवेलियन की राह दिखाई। बिष्ट ने आठ ओवर में 25 रन देकर चार विकेट हासिल किए। इनमें से 3 विकेट तो उन्होंने 41वें ओवर में पांच गेंदों के अंतराल में झटके। शिखा पांडे ने 21 रन पर दो विकेट, दीप्ति शर्मा ने 33 रन पर दो विकेट और झूलन गोस्वामी ने 19 रन पर एक विकेट लिया। इससे पहले भारत की पारी में ओपनर जेमिमा रॉड्रिग्स ने 58 गेंदों आठ चौकों की मदद से 48 रन, कप्तान मिताली राज ने 74 गेंदों में चार चौकों के सहारे 44 रन, विकेटकीपर तानिया भाटिया ने 41 गेंदों में 25 रन और झूलन गोस्वामी ने 37 गेंदों में 30 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से जॉर्जिया एल्विस, नताली शिवर और सोफी एक्लसटोन ने दो-दो विकेट लिए।

संक्षिप्त समाचार

इस साल आईपीएल उद्घाटन नहीं, पुलवामा शहीदों के परिवारों को दी जाएगी धनराशिः सीओए

नई दिल्ली। प्रशासकों की समिति (सीओए) ने फैसला किया है कि आईपीएल में इस साल उद्घाटन समारोह नहीं किया जाऐगा और इसके लिए रखी हुई धन राशि पुलवामा आतंकी हमलों में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के परिवारों को दी जाएगी। आईपीएल का 12वां चरण 23 मार्च से शुरू होगा। प्रशासकों की समिति प्रमुख विनोद राय ने कहा, 'हम आईपीएल में कोई उद्घाटन समारोह नहीं करायेंगे और इसके लिए जितना बजट रखा गया था, वह शहीदों के परिवारों को दिया जाऐगा।' सीओए ने यह फैसला यहां शुक्रवार को हुई बैठक में लिया। गत चैम्पियन चेन्नई सुपरकिंग्स 23 मार्च को आईपीएल के शुरूआती मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर से भिड़ेगा।

हॉकी इंडिया ने एएचएफ के उपाध्यक्ष चुने जाने पर मुश्ताक को दी बधाई

नई दिल्ली । हॉकी इंडिया (एचआई) ने एशियाई हॉकी महासंघ (एएचएफ) का उपाध्यक्ष चुने जाने पर मोहम्मद मुश्ताक अहमद को बधाई दी है। एचआई की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, एएचएफ ने मुश्ताकअहमद को महासंघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। मुश्ताक के अलावा आसिमा अली को एएचएफ के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। मुश्ताक अहमद एक अक्टूबर से 2018 से हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पर कार्यरत हैं। मुश्ताक चार साल तक इस पद पर बने रहेंगे। वह इससे पहले हॉकी इंडिया के महासचिव पद पर काम कर चुके हैं। हॉकी इंडिया ने आसिमा अली को भी निर्विरोध एएचएफ के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य नियुक्त होने पर उन्हें बधाई दी है। अली एक अक्टूबर 2018 से ही हॉकी इंडिया की उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। हॉकी इंडिया के महासचिव राजिंदर सिंह ने मुश्ताक अहमद और आसिमा को अली बधाई देते हुए कहा, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद और उपाध्यक्ष आसिमा अली को एएचएफ कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों के रूप में चुने जाने पर मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दोनों ने देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए हॉकी इंडिया के प्रयास में अपना अहम योगदान दिया है। मुझे उम्मीद है कि अब वे अनुभव से एएचएफ को नए स्तर पर ले जाएंगे।

आतंक के पनाहगारों के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता बीसीसीआई

नई दिल्ली ।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शुक्रवार को पाकिस्तान का नाम लिए बिना क्रिकेट खेलने वाले बाकी देशों से कहा है कि वह आंतक को बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आंतकवादी हमले के बाद बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को पत्र लिखकर कहा है कि वह आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा पर ध्यान दे। इस हमले में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। जौहरी ने जो पत्र लिखा है उसकी प्रति आईएएनएस के पास है जिसमें लिखा है, इस पत्र में बीसीसीआई की वह सभी चिंताएं हैं जो हाल ही में भारतीय जमीन पर हुए हमले के बाद सामने आई हैं। इस हमले में 44 से ज्यादा भारतीय सुरक्षा सैनिकों की जान चली गई थी। पत्र में लिखा है, इस आतंकी हमले के बाद बीसीसीआई को इंग्लैंड में होने वाले विश्व कप और भविष्य में होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों, मैच अधिकारियों की सुरक्षा की चिंता है। उन्होंने कहा, आईसीसी के अधिकतर सदस्यों (जिसमें इंग्लैंड भी शामिल है) ने इस हमले की निंदा की है और भारत का साथ दिया है। बीसीसीआई क्रिकेट खेलने वाले सभी देशों से आग्रह करता है कि वह आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सीईओ ने साथ ही आईसीसी से गुजारिश की है कि वह आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारतीय खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय सुरक्षा मुहैया कराए। उन्होंने लिखा, बीसीसीआई साथ ही आईसीसी क्रिकेट विश्व कप-2019 में भारतीय प्रशंसकों की सुरक्षा को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर करना चाहती है। उन्होंने लिखा, बीसीसीआई को विश्वास है कि आईसीसी और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) आगामी विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों और प्रशंसकों को उच्च स्तरीय सुरक्षा मुहैया कराएगा। बीसीसीआई और प्रशासकों की समिति (सीओए) की बीच शुक्रवार को हुई बैठक इसी साल मई में इंग्लैंड में हाने वाले आईसीसी विश्व कप में पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच पर कोई अंतिम फैसला नहीं ले सकी। चार घंटों तक चली इस बैठक के बाद तीन सदस्यीय सीओए इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेने में असमर्थ रही। सीओए इस मसले पर खुद फैसला लेने से पहले सरकार के फैसले का इंतजार कर रही है। सीओए के चेयरमैन विनोद राय ने कहा, 16 जून का मैच अभी काफी दूर है। हम इस मैच पर फैसला बाद में लेंगे और इस पर सरकार से बात करेंगे।

यूरोपा लीग : प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचा आर्सेनल

लंदन ।

यूरोपा लीग राउंड ऑफ-32 के दूसरे लेग के मुकाबले में गुरुवार रात यहां इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने बेट बोरिसोव को 3-0 से मात देकर प्रतियोगिता के प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बीबीसी के अनुसार, बेलारूस के क्लब के खिलाफ पहले लेग के मैच में आर्सेनल को 1-0 से हार झेलनी पड़ी थी लेकिन दूसरा लेग जीतकर आर्सेनल की टीम 3-1 के कुल योग के साथ अगले दौर में प्रवेश करने में सफल रही। अपने घरेलू मैदान पर खेल रही आर्सेनल पहले मिनट से ही आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आई। मेजबान टीम ने शुरुआत से ही अटैक किया और चौथे मिनट में जाकहर वोल्कोव के ओन ने उसे बढ़त दिला दी। आर्सेनल ने 68 प्रतिशत बाल पोजेशन रखा और किसी भी समय बेट को वापसी का मौका नहीं दिया। पहला हाफ समाप्त होने से पहले मेजाबन टीम ने अपनी बढ़त को दोगुना किया। 39वें मिनट में डिफेंडर शकोड्रान मुस्तिाफी ने मैच का दूसरा गोल दागा। आर्सेनल ने दूसरे हाफ में भी अपने बेहतरीन प्रदर्शन को जारी रखा और अटैकिंग फुटबाल खेली। मैच के 60वें मिनट में आर्सेनल के एक अन्य डिफेंडर सोक्राटिस ने हेडर के जरिए गोल करते हुए स्कोर 3-0 कर दिया। इस गोल ने मेहमान टीम के वापसी के सारे रास्ते भी बंद कर दिए। टूर्नामेंट के अगले दौर के ड्रॉ 22 फरवरी को निकलेंगे।

रणतुंगा को करना पड़ा करारी शिकस्त का सामना, श्रीलंका क्रिकेट के चुनाव में हारे

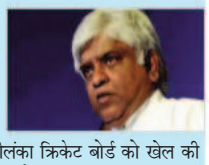

कोलंबो। विश्व कप विजेता कप्तान अर्जुन रणतुंगा को गुरूवार को श्रीलंका के राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड के चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा जिससे उनकी खेल को भ्रष्टाचार मुक्त करने की उम्मीद को झटका लगा। पचपन वर्षीय रणतुंगा ने दो में से एक उपाध्यक्ष पद के लिये चुनाव लड़ने का फैसला किया लेकिन वह मतदान के बाद तीसरे स्थान पर रहे। उनके भाई निशांत को भी हार का मुंह देखना पड़ा जिन्हें सचिव के लिये नामांकित किया गया था। वर्ष 1996 विश्व कप में श्रीलंका की अगुवाई कर टीम को खिताब दिलाने वाले रणतुंगा बोर्ड से भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश में चुनाव में जीत हासिल करने के प्रयास में जुटे थे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने हाल में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को खेल की सबसे भ्रष्ट राष्ट्रीय संस्था करार दिया था। पूर्व कप्तान रणतुंगा सरकार में मंत्री भी हैं और वह 30 मई से इंग्लैंड में शुरू होने वाले विश्व कप से पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में आने की उम्मीद लगाए थे। रणतुंगा के सहयोगी जयंत धर्मदास भी श्रीलंका क्रिकेट अध्यक्ष बनने की मुहिम में विफल रहे। वह रणतुंगा के चिर प्रतिद्वंद्वी और एसएलसी के पूर्व प्रमुख तिलंगा सुमतिपाला के वफादार शम्मी सिल्वा से हार गए। सुमतिपाला दो साल से ज्यादा समय तक इस पद पर काबिज रहे लेकिन 2018 के शुरू में हटने के बाद उन्होंने फिर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया।

पाक निशानेबाजों का वीजा रद्द करने के मामले में IOC ने भारत से छीनी खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी

नई दिल्ली-

इंटरनैशनल ओलिंपिक कमिटी ने दिल्ली में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी निशानेबाजों को वीजा न देने के बाद भारत को भविष्य में आयोजित होने वाले किसी भी ओलिंपिक और खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी से भी अलग कर दिया है। भारत की तरफ से लिखित आश्वासन के बाद आईओसी ने विश्व कप की मेजबानी नहीं छीनी है। नैशनल राइफल असोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के प्रस्ताव के बाद आईओसी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। पाकिस्तान ने कोटा के तहत 25मीटर रैपिड फायर इवेंट में भारत के द्वारा 2 पाकिस्तानी शूटर्स को वीजा देने से इनकार के बाद यह प्रस्ताव दिया था। पुलवामा अटैक के बाद देश के माहौल को देखते हुए यह फैसला लिया गया। आईओसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया, भारतीय एनओसी, आईओसी और आईएसएसएफ के आखिरी वक्त तक किए प्रयासों के बाद भी पाकिस्तानी टीम के प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कोई रास्ता नहीं बन सका। यह स्थिति किसी भी तरह के भेदभाव नहीं करने के आईओसी के मूल चार्टर के खिलाफ है। आईओसी की प्रतिबद्धता है कि मेजबान देश में आनेवाले सभी खिलाड़ियों को किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना निष्पक्ष और समानता के माहौल में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिले। पाकिस्तान ने अपने देश के निशानेबाजों को भारतीय वीजा न मिलने के बाद आईओसी से इसकी शिकायत की थी। पुलवामा आतंकी हमले में 40 जवान शहीद होने के बाद भारत ने निशानेबाजों को वीजा देने से इनकार किया था। बयान में भारत को भविष्य में खेलों की मेजबानी से दूर रखने के फैसले के बारे में जानकारी दी गई। आईओसी के अनुसार, मौजूदा घटनाक्रम के परिणाम के तहत आईओसी एग्जिक्यूटिव बोर्ड ने यह फैसला किया है कि भारतीय एनओसी और सरकार के साथ भविष्य में किसी भी खेल प्रतियोगिता और ओलिंपिक से संबंधित प्रतियोगितायओं के आयोजन को लेकर सभी चर्चाएं पूरी तरह से स्थगित की जाती हैं।

भारत के खिलाफ अनुकूल होना ही अहम होगाः ख्वाजा

मेलबर्न। आस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा का मानना है कि भारत के खिलाफ सीमित ओवर की श्रृंखला के दौरान अनुकूलन क्षमता अहम साबित होगी और कहा कि वे देश में खेलने के बीते अनुभव से सीख लेने की कोशिश करेंगे। आस्ट्रेलियाई टीम भारत दौरे की शुरूआत रविवार को विशाखापत्तनम में पहले ट्वेंटी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से करेगी और ख्वाजा का मानना है कि विकेट बल्लेबाजी के लिये अच्छा होगा। ख्वाजा भारत में राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स के लिये इंडियन प्रीमियर लीग में छह मैच खेल चुके हैं जो अब भंग हो चुकी है। उन्होंने कहा, ''मैं उस टी20 (विश्व कप) में खेला था और विकेट सचमुच ही बहुत अच्छा था। ख्वाजा इस समय हैदराबाद में हैं और उन्होंने कहा, ''मेरे हिसाब से धर्मशाला का विकेट थोड़ा ज्यादा स्पिन हुआ था, मोहाली और बेंगलुरू में विकेट बल्लेबाजी के लिये काफी अच्छा था। उन्होंने कहा, ''आपको यहां जिस भी सतह पर खेलने को मिलेगा, आपको उसके अनुकूल होना होगा। आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ियों ने बीते समय में भारत में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है इसलिये मुझे लगता है कि हमें उस अनुभव से मदद मिल सकती है। एजेंसी

तीन से दस मार्च के बीच होगी सूरत में फुटबाल प्रीमियर लीग

सूरत। क्रिकेट की तरह सूरत समेत गुजरात में फुटबाल को बढवा देने के लिए आगामी 3 से 10 माच क दौरान सूरत फूटबाल प्रीमीयर लीग का आयोजन किय जा रहा ै। वेसू स्थित डीआरबी स्पोर्टस काम्पेलक्ष में होने वाले इस टूामेंट में टाइटल के लिए आठ टिमों के बीच हक्कर होगी। इन टीमों में सर्फि सूरत के ही 100 से अधिक खिळआड़ी हिस्सा लेंगे। आयोजक अक्षत बागेचा ने बताया कि लीग का आयोजन आठ कंपनियों के सहयोग से किया जा रहा है। प्रत्येक कंपनी की एक टीम है जिनके कप्तान ूरत केनामी फुटबाल जावेद सफेदा, इम्तियाज सोनी, प्रजय नायक, तालक मिचला, मासूम मिश्रा, जाहीद सफेदा, पिंकल अब्राहम व जैशील शाह है। ये सभी निलामी में रजिर्स्टड स्थानीय खिलाड़ियों का चयन कर अपनी टीमों बनाएंगे। टूर्नामेंट हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को उनके स्तर के हिसाब से मैच फीस दी जाएगी। उन्होंने बताया कि रंदेर क्षेत्र में फुटबाल का क्रेज है और वहां प्रतियोंगिताएं भी होती है लेकिन ये एक क्षेत्र विशेष तक समित होने के कारण शहर के अन्य खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा सामने लाने का मौका नहीं मिल पाता है। पुरे शहर के खिलाड़ियों को एक बड़ा प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस लीग की शुरुआत की गई है।

केंद्रीय मंत्री चौधरी देंगे श्रद्धांजलि

सूरत। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद वीर जवानों के सम्मान में सर्व प्रवासी राजस्थानी समाज की ओर से सोमवार को शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में केंद्रीय विधि, न्याय एवं कॉर्पोरेट राज्यमंत्री पीपी चौधरी विशेष रूप से मौजूद रहकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे।

सीरवी समाज के अध्यक्ष हेमाराम पंवार ने बताया कि पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में शहीद सम्मान समारोह का आयोजन सर्व प्रवासी राज-स्थानी समाज की ओर से सोमवार रात साढ़े आठ बजे परवत पाटिया में आईमाता रोड पर सीरवी समाज भवन में किया जाएगा। इसमें केंद्रीय राज्यमंत्री पीपी चौधरी समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहेंगे और शहीदों के प्रति श्रद्धाभावना प्रकट करेंगे। समाज के मीडिया प्रभारी पेमाराम सोयल ने बताया कि बाद में केंद्रीय राज्यमंत्री चौधरी सर्किट हाउस में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे।

हाथों में आज सजेगी मेहंदी

अग्रवाल विकास ट्रस्ट की ओर से दिव्यांग सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन मंगलवार को किया जाएगा और इसमें 21 दिव्यांग जोड़े एक-दूसरे के जीवनसाथी बनेंगे। सम्मेलन में शामिल होने वाली दिव्यांग युवतियों व उनके परिजनों के हाथों में मेहंदी सोमवार को रचाई जाएगी। मेहंदी रस्म के दौरान आयोजक ट्रस्ट की महिला शाखा व युवा शाखा की सदस्य महिलाएं व युवतियां भी मौजूद रहेगी।

भारतमाता का किया शृंगार

लोकमान्य सेवा ट्रस्ट की ओर से संत रविदास महाराज व छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष में रविवार को पांडेसरा के देवकीनंदन स्कूल प्रांगण में सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान बाबा सत्यनारायण मोर्या ने भारत माता की झांकी सजाई और अनूठे तरीके से आरती की। कार्यक्रम के दौरान आयोजक ट्रस्ट के अलावा अस्मिता सेवा ट्रस्ट, छत्रपति शिवाजी स्मारक समिति, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन गुजरात, यूथ फॉर गुजरात, बापा सीताराम फाउंडेशन, देवकीनंदन स्कूल, महाराष्ट्र कुणबी समाज उन्नति संघ आदि संस्थाओं के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे।

धारा 35 ए तत्काल हटाई जाए: कुलश्रेष्ठ

नानपुरा के जीवन भारती स्कूल के ऑडिटोरियम में रविवार सुबह भारत की आंतरिक घेराबंदी विषय पर परिसंवाद का आयोजन किया गया। इसमें वक्ता के रूप में आमंत्रित रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व अधिकारी आरएसएन सिंह व राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने श्रोताओं को बताया कि धारा 35 ए को संविधान से तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए अन्यथा जम्मु-कश्मीर में फैला आतंकवाद व जेहाद पूरे देशभर में फैल जाएगा। परिसंवाद के दौरान दोनों ही वक्ताओं ने आतंकवाद व राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में कई जरूरी तथ्यों को सबके सामने रखा। बगैर किसी संस्था के इस आयोजन में युवराज पोखरणा, भरत सावलिया, कीर्ति पटेल, अजयसिंह, सत्येन पाठक आदि ने सक्रिय योगदान दिया।

पाटण एसओजी-हारीज पुलिस की छापेमारी

हारीज तहसील में अरंडी की आड़ में गांजा-अफीम की खेती

पीपलाणा गांव में खेत में बुवाई की गई ५०० किलो गांजा और अफीम का जत्था जब्त : किसान गिरफ्तार

अहमदाबाद,२४ फरवरी।

पाटण जिले की हारीज के पीपलाणा गांव में पाटण एसओजी और हारीज पुलिस ने पीपलाणा गांव में छापेमारी करके गांजा-अफीम की खेती के घोटाले का पर्दाफाश करने से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। पुलिस ने यह पूरे मामले में आरोपी किसान जीवणजी सरतनजी ठाकोर को गिरफ्तार करके इसके खेत से ५०० किलो गांजा और अफीम का जत्था जब्त किया गया। पुलिस अब किसान ने किसके इशारे पर और किस चेन थ्रू खेत में गांजा-अफीम की खेती शुरू की थी यह पूरे मामले में अन्य कौन-कौन शामिल है यह सहित के मुद्दे की जांच शुरू की है। इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार, पाटण जिले की हारीज के पीपलाणा गांव में एक किसान ने गांजा की बुवाई की यह जानकारी के आधार पर पाटण एसओजी हारीज पुलिस को मिली थी। इसके आधार पर पाटण एसओजी और हारीज पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर दो से ढाई विधा खेती प्लोट में अरंडी की आड़ में बुवाई किया गया गांजा और अफीम का ज त्था पकड़े जाने से सनसनी मच गई। हारीज तहसील के पीपलाणा के किसान जीवणजी सरतानजी के भलाणा मार्ग पर स्थित तालाब बगल के दो से ढाई विद्या के खेत में अरंडी की बुवाई के बीच गांजा तथा अफीम की खड़ी फसल बुवाई किए जाने की बात सामने आई थी। पाटण एसओजी पीआई डीएच. जाला, राधनपुर सीपीआई राठवा और हारीज पीएसआई एचएल. जोशी तथा पुलिस स्टाफ ने दोपहर के समय में संयुक्त छापेमारी करने से करीब ५०० किलो ग्रीन गांजा और गाजा भेगोज अफीम के पौधे जब्त करके किसान जीवणजी सरतनजी ठाकोर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस भी इस प्रकार से खुले खेत में बिंदास रूप से गांजा-अफीम उगाने के काम से आश्चर्य में पड़ गई थी। हालांकि गांजा-अफीम की खेती नहीं दिखाई दे इसके लिए चारों तरफ अरंडी की आड़ का मदद आरोपी ने लिया था लेकिन आखिर में वह गिरफ्तार हो गया था।

मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की प्रेरक उपस्थिति में

किसान सम्मान निधि के लाभों का भुगतान राजकोट से प्रारंभ

राजकोट के डेढ़ लाख सहित राज्य के ४२.४७ लाख किसानों को २ हजार की पहली किश्त का भुगतान होगा

अहमदाबाद,२४ फरवरी।

फिलहाल में केंद्रीय बजट में जारी किए गए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूपी के गोरखपुर से प्रारंभ कराया इसके साथ ही गुजरात में यह योजना का राजकोट से मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की प्रेरक उपस्थिति में शुभारंभ हुआ है। यह योजना के तहत राज्य के ४२.४७ लाख किसानों को सम्मान निधि के तहत कुल ६ हजार रुपये में से पहली किश्त के तहत २००० रुपये भुगतान का प्रारंभ किया गया है। राजकोट जिला पंचायत द्वारा हेमू गढवी हॉल में आयोजित किए गए कार्यक्रम में आत्म योजना के साथ जुड़ी हुई महिला किसान बड़ी संख्या में उपस्थित हुई थी। कार्यक्रम में पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का लाइव प्रसारण किया गया।जिसे उपस्थित सभी लोगों ने उत्साह से सुना और प्रधानमंत्री द्वारा कई विषयों पर पेश किए गए विचारों को सुनकर मंथन किया गया। यूपी के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कार्यक्रम का भी लाइव प्रसारण किया गया। जिसमें प्रथम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण पेश हुआ था। बाद में प्रधानमंत्री ने पूरे देश में से आये किसानों को हाथोंहाथ यह योजना का लाभ दिया गया था। जिसमें गुजरात के किसान भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने भी जोश के साथ संबोधित किया।

प्रधानमंत्री के भाषण में मुख्य बात चाहिए तो उन्होंने बिचौलिए को दूर करके गरीबों को उनके अधिकार सीधा दिए जाने का तथा किसानों की आय आगामी २०२२ तक में दोगुना करने की बात कही थी। प्रधानमंत्री के यह भाषण को मुख्यमंत्री विजय रुपाणी, शिक्षामंत्री भूपेन्द्रसिंह चूडासमा, कृषिमंत्री आरसी. फलदू ने भी सुना। इसके बाद यह योजना का प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राजकोट जिले के प्रथम लाभार्थी बनने का मोविया गांव के किसानों को मिला। राजकोट जिले को कुल १४७१३४ किसानों को अभी तक में यह योजना के तहत शामिल किया गया है।

अहमदाबाद शहर के हेल्मेट चार रास्ता क्षेत्र में आग लगने से फायरब्रिगेड की टीम तुरंत घटनास्थल पहुंच गई थी। लोगों में भी उत्तेजना फैल गई।

आग दूसरी मंजिल तक फैलने से भगदड़

रूद्र आर्केड में बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में आग

अहमदाबाद,२४ फरवरी।

शहर के हेल्मेट चार रास्ते के पास स्थित रूद्र आर्केड कॉम्प्लेक्स में रविवार को बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम सेंटर में लगी भीषण आग की वजह से स्थानीय लोगों और दुकानदारों में भगदड़ मच गई। आग ग्राउंड प्लस पहले और दूसरी मंजिल पर पांच से सात दुकानों तक पहुंचने से यह दुकानों को काफी नुकसान हुआ। घटना की जानकारी मिलने से मेमनगर फायर स्टेशन से फायरब्रिगेड के जवानों का काफिला तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया और समय से दुकानों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थल पर भेजकर कुछ ही घंटों में आग को नियंत्रण में ले लिया गया। आग की यह घटना मामले में एडिशनल चीफ फायर ऑफिसर राज `श भट्ट ने बताया कि, शहर के हेल्मेट चार रास्ते के पास स्थित रूद्र आर्केड कॉम्प्लेक्स में रविवार को दोपहर में बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम सेंटर में शोर्ट सर्किट या अन्य किसी वजह से आग लगी थी, जि समें पूरा एटीएम सेंटर जलकर खाक हो गया था। विशेष तो, एटीएम मशीन भी जलकर खाक हो जाने से अंदर रखी गई नोटों की करंसी भी जल गई होने की पूरी संभावना है। जिसकी वजह से बैंक को लाखों रुपयों का नुकसान होने का अनुमान है। लेकिन आग की लपटे नीचे ग्राउंड फ्लोर से लेकर पहले और दूसरी मंजिल की पांच से सात दुकान इसकी चपेट में आ गई थी। जिसकी वजह से ऊपर की मंजिल पर एक डेंटल क्लीनिक सहित अन्य दुकानों में फर्निचर, फ्रेम, बिल्डिंग की इमारत को गंभीर रूप से नुकसान हुआ। आग की वजह से स्थानीय दुकानकारों और लोगों में भगदड़ मच गई। हालांकि फायरब्रिगेड के जवानों ने सभी लोगों को सुरक्षित स्थल पर भेजने से कोई घायल या जानहानि नहीं हुई थी। फायरब्रिगेड के जवानों ने काफी प्रयास के बाद कुछ ही घंटों में आग को नियंत्रण में ले लिया गया यह एडिशनल चीफ फायर ऑफिसर राजेश भट्ट ने बताया।

बोडेली की मोरखला गांव में ट्रक ने ३ युवकों को कुचला

अहमदाबाद,२४ फरवरी।

छोटा उदेपुर जिले के बोडेली की मोरखला गांव में रविवार को दोपहर में तेजी से आ रही ट्रक के चालक ने बाइक पर जा रहे तीन युवकों टक्कर मारने से वह गंभीर रूप से घायल हो गये थे। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए तीन बाइकसवार युवकों की मौत हो जाने की आशंका रही है। हालांकि, स्थानीय पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। घातक दुर्घटना करने के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर घटनास्थल से फरार हो गया था, इसी वजह से पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने के लिए खोजबीन शुरू कर दी है।

दुर्घटना की वजह से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई और शोक की लहर फैल गई।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)